an>

Title: Need to prevent illegal construction in Northern India including Delhi in view of the possibility of earthquakes in the country.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, नेपाल में आये भूकम्प से अभी तक हम लोग सबक नहीं ले पाये हैं, जबकि दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत भूकम्प के मुहाने पर बैठा हुआ है। दिल्ली में एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर लगभग 70 परसेंट ऐसे मकान हैं, जो भूकम्प की चपेट में कभी भी आ सकते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, जो विशेषकर भूकम्प से ही जुड़ा हुआ है। हमारी भारत सरकार ने बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश में 28 राजकीय कन्या महाविद्यालय देने का कार्य किया है। मैं अपनी सरकार की माननीय मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन आज पीड़ा होती है, भूकम्प की इस त्रासदी को देख करके कि आज जो 28 कन्या महाविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने दिये हैं, उन 28 महाविद्यालयों का टेंडर मनमाने तरीके से किया गया है और उसमें यह आंकलन नहीं कराया गया है कि भूकम्परोधी वह भवन बन रहा है कि नहीं, जहां हमारे भारत का भविष्य कन्याएं पढ़ने जाएंगी, जो हमारी बहनें पढ़ने जाएंगी, वह बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है।

अतः मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार की तरफ आग्रह करना चाहूंगा कि विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा कोई एक तकनीकी कमेटी स्थापित की जाये और जहां-जहां सरकारी भवन भूकम्प के मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बन्द करा करके, जबकि पैसा उसमें भूकम्परोधी भवन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है, को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

मैं आपके माध्यम से सरकार का उत्तर प्रदेश पर मैं विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा, चूंकि बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राजकीय कन्या महाविद्यालयों को बनाने की खातिर दी है व 70 परसेंट धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, लेकिन उसमें भूकम्परोधी मानकों का पालन नहीं हो रहा है। वहां पर इसे पालन करवाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.